सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-32 अंक-17 7 से 21 सितम्बर, 2017 मुख्य संपादक कॉमरेड प्रभास घोष कुल पृष्ठ 8 मूल्य : 2 रुपये

कॉमरेड माओ त्से-तुंग लाल सलाम

26.12.1893 – 9.9.1976

''हमने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन पराजित वर्ग संघर्ष जारी रखेगा। इसके सदस्य अभी भी चारों तरफ हैं और अपना अस्तित्व रखते हैं। इसलिए हम दशकों तक इसे अन्तिम जीत, नहीं कह सकते। हमें अपनी सतर्कता नहीं खोनी चाहिए। लेनिनीय नजरिये से एक समाजवादी देश में अन्तिम जीत के लिए न केवल देश के सर्वहारा और व्यापक आम जनता के प्रयासों की जरूरत होती है, बल्कि विश्व क्रान्ति की जीत और इस धरती पर से मानव द्वारा मानव के शोषण के खात्मे पर भी निर्भर होती है ताकि समस्त मानवजाति को मुक्ति मिल सके। फलस्वरूप, हल्के-फुल्के दिल से हमारे देश में क्रान्ति की अन्तिम जीत की बात करना गलत है; यह लेनिनवाद के खिलाफ बात है और तथ्यों की पुष्टि नहीं करती है। ''

– माओ त्से-तुंग

(15-04-1969; सांस्कृतिक क्रान्ति के बारे में दिशा-निर्देशों में उद्धृत)

आर.बी.आई. की सालाना रिपोर्ट से नोटबन्दी की नाकमी हुई बेनकाब

एसयूसीआई (सी) ने लोगों से एकजुट होने व आर्थिक हमलों को विफल करने का किया आह्वान

31 अगस्त, 2017 को एसयूसीआई (सी) के महासिचिव कॉ. प्रभाष घोष ने निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया :

हालिया आरबीआई की सालाना रिर्पोट ने साफ तौर पर सामने ला दिया है कि नोटबन्दी के अपने बेतुके कदम के समर्थन में बीजेपी द्वारा पेश किये गये तथाकथित औचित्य जैसे कालेधन को बाहर निकालना और व्यवस्था से नकली नोटों का सफाया करना, असल में एक झांसा था और स्पष्ट रूप से आम आदमी की कीमत पर एकाधिकारी पूँजीपतियों के निहित स्वार्थ को साधने के छिपे ऐजेण्डे को पुष्ट करने पर लक्षित था। चलन से बाहर किये गये नोटों का 98 प्रतिशत से भी ज्यादा बैंकिग सिस्टम में वापस आ गया है। यह इस बात को पुनः पुष्ट करता है कि कैसे सरकार ने गरीबों विशेषकर वंचितों और पददलितों के सर पर तलवार लटका दी थी, पहले से ही बदहाल उनके आर्थिक जीवन को और भी तबाह कर दिया, अनेकों बेगुनाह जाने ले ली और किसानों दिहाड़ी मजदूरों, प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों, आम दुकान मालिकों और छोटे व्यपारियों की आजीविका को स्थाई रूप से छीन लिया जो अपनी आमदनी के लिए पूरी तरह से नकद लेन-देन पर निर्भरशील हैं।

नोटबन्दी के पीछे की घृणित साजिश का पर्दाफाश करते हुए हमारी पार्टी ने गत नवम्बर में स्पष्ट तौर से कहा था कि आज पूँजीवाद न केवल भ्रष्ट हो गया है बल्कि नितांत अमानवीय भी हो गया है, जिसे लोगों की दुदर्शा, मुसीबतों या आंसुओं से लेशमात्र भी सरोकार नहीं है क्योंकि इसका एकमात्र उदेश्य है लोगों को ठगना, उनकी जेब से आखिरी दमड़ी तक खसोट लेना और उनकी बढ़ती बदहाली-कंगाली पर एकाधिकारी दैत्यों को मालामाल करते जाना।

हमारी लोगों से पुरजोर अपील है कि वे पूँजीवादी सरकार के चाशनी सने शब्दो के झांसे में न आयें और तुरन्त अपनी एकता को सुदृढ़ करें ताकि उन पर हो रहे ऐसे आर्थिक हमलों को संयुक्त, संगठित, सचेत प्रतिवाद आन्दोलन से रोका जा सके।

नारी-उत्पीड़न का देश भर में विरोध

महिलाओं पर बढ़ते अपराध, बलात्कार, हत्या, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, नशाखोरी व अश्लीलता, साइबर क्राइम, ऑनर किलिंग आदि पर कारगर रोक लगाने और वर्मा कमीशन की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग को लेकर 22 अगस्त को ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) के बैनर तले देशव्यापी विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया था। अखिल भारतीय विरोध दिवस के क्रम में एआईएमएसएस की ओर से देश भर में धरने व विरोध प्रदर्शन आदि कार्यक्रम लिये गए।

दिल्ली : ए.आई.एम.एस.एस. की दिल्ली कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री निवास पर मार्च किया गया। मुख्यमंत्री श्री अरविंद

शेष पृष्ट 3 पर

दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ज्ञापन की मांगों पर बातचीत करते हुए एआईएमएसएस प्रतिनिधिमण्डल

लेनिन और रूस की नवम्बर क्रान्ति

प्रभास घोष

(11 जून 2017 को झारखण्ड के घाटशिला स्थित 'मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष चिंतनधारा अध्ययन केन्द्र' में पार्टी की उड़ीसा राज्य कमेटी की तरफ से आयोजित एक सभा में पार्टी के महासचिव कॉ. प्रभास घोष ने महान नवम्बर क्रान्ति के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 'नवम्बर क्रान्ति और लेनिन' विषय पर एक संक्षिप्त वक्तव्य रखा जो पार्टी के बंगाली मुखपत्र गणदाबी के 21 जुलाई के अंक में प्रकाशित हुआ। इसी को हिन्दी में रूपांतरित करके यहां छाप रहे हैं। अनुवाद में कमी-खामी के लिए पूर्णतः हम जिम्मेदार होंगे-सम्पादक सर्वहारा दृष्टिकोण)

आज की इस सभा में किसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं नहीं आया था। मैं आपकी चर्चा सुनने के लिए ही आया था। चर्चा सुनते-सुनते लगा कि नवम्बर क्रान्ति में महान लेनिन की भूमिका के बारे में कुछ शब्द कहने की जरूरत है। इस बारे में हमारे महान शिक्षक कॉमरेड शिवदास घोष के बेशकीमती वक्तव्य कॉमरेडों के सामने हैं और बाद में पार्टी के प्रकाशित वक्तव्य कॉमरेडों ने पढ़े हैं। मैं क्रान्तिपूर्व अवधि में कॉमरेड लेनिन द्वारा निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका के कुछेक पहलूओं का यहां उल्लेख करूंगा।

आप सभी जानते हैं कि मार्क्स-एंगेल्स द्वन्द्वात्मक भैतिकवाद की बुनियाद रख गये हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे गये हैं और सत्य को जांचने-परखने का रास्ता दिखा गये हैं तथा इस दार्शनिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके राजनीति, अर्थव्यवस्था, इतिहास, समाज, साहित्य-संस्कृति आदि ज्ञान-विज्ञान की हर शाखा में बेशुमार योगदान कर गये हैं। वे समसामयिक नाना समस्याओं और घटनाओं पर बहुत ही शिक्षाप्रद रोशनी डाल गये हैं। दुनिया की मजदूर क्रान्ति की तैयारी के हथियार प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को

शेष पृष्ट 2 पर

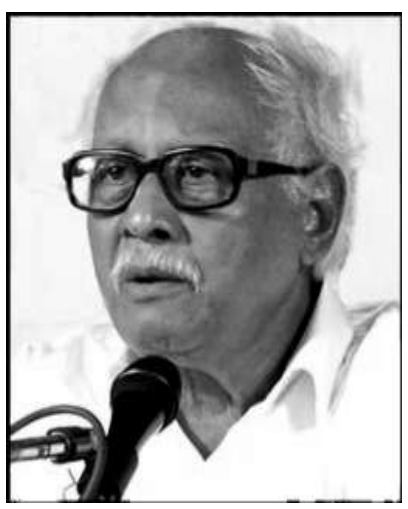

लेनिन और नवम्बर क्रान्ति

(पृष्ठ 1 का शेष)

मार्क्स ही बना गये थे। उस संगठन के पथ-भ्रष्ट हो जाने पर एंगेल्स ने द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय गठित किया था। मार्क्स की मृत्यु के बाद एंगेल्स 12 साल जिन्दा रहे थे। उनके नेतृत्व में द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय ने सही ढंग से काम किया था। उसके बाद भी कुछ दिन ठीक ठाक चला था। इस द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय के नेतृत्व में जर्मनी, इटली फ्रांस और इंग्लैण्ड में कई शक्तिशाली मजदूर वर्ग की पार्टी गठित हुई थी। लेनिन जब मार्क्सवादी आन्दोलन में जुड़े तब द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय एक शक्तिशाली संगठन था और उसके नेताओं को वे शिक्षक के रूप में मानते थे। फिर रूस में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी (आरएसडीएलपी) नाम से मार्क्सवादी पार्टी गठित हुई थी और उसमें लेनिन शामिल हुए थे। द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय के नेता थे काउत्स्की और बर्नस्टीन और ऐसे ही कई नेता। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के नेता प्लेखानोव सहित और भी कई नेता थे। इन नेताओं के खिलाफ बाद के दौर में मार्क्सवाद की प्राणसत्ता की रक्षा के लिए लेनिन ने डट कर संघर्ष किया था और इसकी सही व्याख्या पेश की थी। इस क्षेत्र में उन्होंने एक ऐतिहासिक भूमिका निभायी थी। उस समय वे द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय में लगभग अपरिचित थे। रूस में भी बहुत ज्यादा जाने नहीं जाते थे। उम्र में भी उन लोगों से छोटे थे इसलिए एक बार जरा सोचकर देखिए उस उम्र में ही मार्क्सवाद की कितनी उन्नत समझदारी हासिल कर पाने से, शोषित वर्ग के प्रति कितनी गहरी हमदर्दी रहने से, सत्यनिष्ठा, सच्चा साहस और अटल दृढ़ता रहने से यह ऐतिहासिक लड़ाई चलाना लेनिन के लिए सम्भव हुआ था। मैंने पहले ही कहा है कि पहले उनको नेता, शिक्षक के तौर पर भी लेनिन ने माना था। जिन्होंने लेनिन की किताबें पढ़ी हैं उन्होंने देखा होगा कि किस तरह द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय के नेतागण मार्क्सवाद को विकृत कर रहे थे, उसकी गलत व्याख्या कर रहे थे।

लेनिन ने कैसे की गलत व्याख्या से मार्क्सवाद की रक्षा

तब लेनिन ने इन नेताओं के बारे में चर्चा करते हुए यह टिप्पणी की थी : 'When they were Marxist' अर्थात् जब वे मार्क्सवादी थे तब उनकी व्याख्या सही थी लेकिन बाद में द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय के ये नेता मार्क्सवाद से भटक गये थे और गलत बयानी कर रहे थे। साम्राज्यवाद के युग में बड़ी-बड़ी साम्राज्यवादी ताकतों ने दूसरे देशों को लूटकर भारी धन-सम्पदा इकट्ठी कर ली थी। इस धन का एक हिस्सा इस्तेमाल करके साम्राज्यवादी शासकों ने यूरोप के मजदूर नेताओं को तरह-तरह से रिश्वत देकर खरीद लिया था और बुर्जुआ पार्लियामेन्ट के मेम्बर बनना, भाषणबाजी करना, भाषण छापना, नाम होना, सब मिलाकर तृप्तिदायक संसदीय परिवेश के अन्दर द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय के नेता संसदीय राजनीति के भंवर में डूब गये थे और अपना क्रान्तिकारी चरित्र खो बैठे थे। अर्थात् यूरोप के मजदूर आन्दोलन के नेता जो द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय से जुड़े हुए थे, वे शासक साम्राज्यवादियों के हाथों बिक गये थे। फलस्वरूप इनके अन्दर समझौतापरस्ती, क्रान्तिकारी संघर्ष से विमुखता और भ्रष्टाचार ने यूरोपीय मजदूर आन्दोलन के ज्यादातर नेताओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लेनिन यह समझ पाये थे। लेनिन ने मार्क्सवाद और विचार-विश्लेषण की मार्क्सवादी पद्धति के सारतत्व को आत्मसात कर लिया था और संघर्षों के जरिए वस्तुगत परिस्थिति के सही आंकलन में सच्चाई पर पहुंचने के लिए मार्क्सवाद की शिक्षाओं को लागू करने की क्षमता अर्जित कर ली थी। संक्षेप में यूं कहें कि उन्होंने सीख लिया था कि एक ठोस परिस्थिति में मार्क्सवाद को सही ढंग से और ठोस रूप में कैसे लागू करें। फलस्वरूप विपथगामियों के हाथों से मार्क्सवाद की उन्होंने रक्षा की थी। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनकी यह भूमिका ऐतिहासिक है। जहां तक मेरी जानकारी है 'रिविजनिज्म' (संशोधनवाद) शब्द का इस्तेमाल लेनिन ने ही सबसे पहले किया था। उन्होंने ही दिखाया था कि वे नेता पथभ्रष्ट होकर मार्क्सवाद को 'रिवाइज' या संशोधित कर रहे हैं, इसलिए संशोधनवादी हैं। लेनिन ने कहा था कि ये पतित नेता मार्क्सवाद का विकृतिकरण, मिथ्याकरण करके इसके क्रान्तिकारी सारतत्व से इसे महरूम करके मार्क्सवाद का विकृत संस्करण फैला रहे हैं जिसे पूंजीपति सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं अर्थात् जिस विकृत व्याख्या पर बुर्जुआ वर्ग को कोई एतराज नहीं होगा। इसलिए लेनिन ने कहा था कि ये नेता मार्क्सवाद की गलत व्याख्या कर इसका संशोधित संस्करण पेश कर रहे हैं। मार्क्सवाद की क्रान्तिकारी समझ क्या है? मार्क्सवाद की यथार्थ समझ क्या है? दुनिया में उस समय लेनिन ने ही सबसे पहले यह विश्लेषण करके दिखाया था। लेनिन की अन्यतम बड़ी और ऐतिहासिक भूमिका यही है।

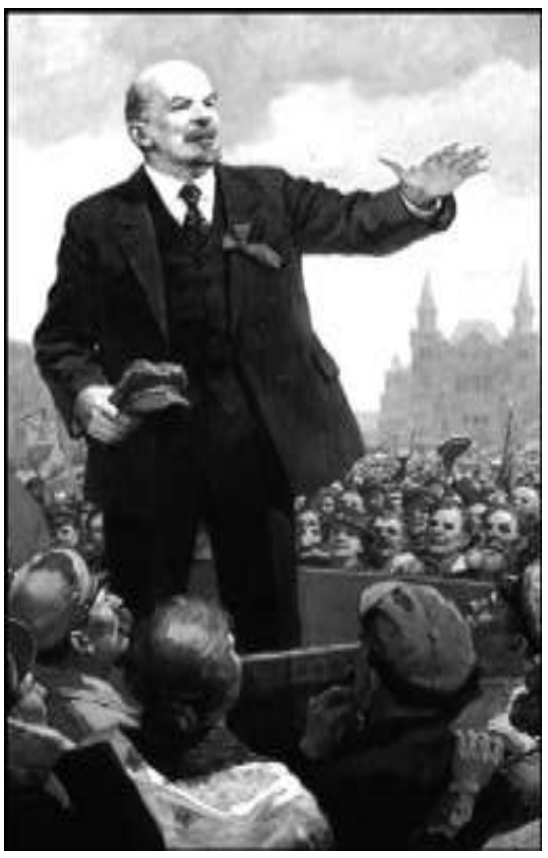

लेनिन का प्रतिपादन : पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है साम्राज्यवाद

एक और क्षेत्र में भी लेनिन की ऐतिहासिक भूमिका रही है। मार्क्स ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद को साम्राज्यवाद से पहले के युग में प्रयोग किया। मार्क्स-एंगेल्स साम्राज्यवाद देख नहीं पाये। एंगेल्स की मृत्यु के कुछ साल बाद ही पूँजीवाद ने एकाधिकारी पूँजी, वित्तीय पूँजी को जन्म देकर साम्राज्यवादी चरित्र हासिल करके और पिछड़े हुए देशों में वित्तीय पूँजी निवेश करके सस्ते श्रम का शोषण और कच्चे माल का दोहन करके उन देशों को लूटा था। लेनिन ने दिखाया कि पूँजीवाद एकाधिकारी पूँजीवाद में विकसित हो गया है, साम्राज्यवादी चरित्र हासिल करके विकास के सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गया है। अब उसके क्षय का युग है। इस साम्राज्यवादी युग की विशेषताएं और चरित्र क्या-क्या हैं, मजदूर क्रान्ति की राजनीति और रणकौशल क्या है? यह भी लेनिन ने ही दिखाया था। जिसकी वजह से महान स्तालिन ने विश्लेषण करके दिखाया था कि लेनिनवाद है साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रान्ति के युग का मार्क्सवाद। मार्क्स के युग में मार्क्स ने सही ही कहा था कि उन्नत पूँजीवादी देशों में पहले क्रान्ति होगी। जबकि लेनिन ने मार्क्सवादी विचारधारा को इस्तेमाल करके दिखाया था कि उन्नत पूँजीवादी देशों ने साम्राज्यवादी स्तर पर पहुंचकर उपनिवेशों को लूटकर अपने देश के मजदूर को ज्यादा-बोनस देकर काफी हद तक उनकी लड़ने की मानसिकता नष्ट कर दी है, उन्हें भ्रष्ट (करप्ट) कर दिया है। अब जिन सब देशों में ज्यादा शोषण हो रहा है, जनता ज्यादा अत्याचारित हो रही है उन सब सापेक्षत: पिछड़े हुए देशों में ही पहले क्रान्ति होगी। उसके बाद विकसित पूँजीवादी-साम्राज्यवादी देशों में संकट और तीव्रतर होगा, क्रान्ति का मैदान तैयार होगा। द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय के नेताओं ने लेनिन पर आरोप लगाया कि तुम मार्क्स को नहीं मानते हो। लेनिन ने कहा कि तुम मार्क्सवाद पर लेटे हुए हो, खड़े नहीं हो। लेनिन ने दिखाया पिछड़े देशों में ही विश्व पूँजवाद-साम्राज्यवाद की जंजीर पहले टूटेगी। इन सब देशों में जितनी क्रान्ति होगी विकसित पूँजीवादी देश उतने ही संकटग्रस्त होंगे। उन देशों के मजदूर वर्ग भी उतने ही क्रान्ति के पथ पर चलने लगेंगे। यह है लेनिन का एक और महत्वपूर्ण योगदान।

जैसाकि मैंने पहले ही जिक्र किया है, लेनिन ने ही पहले पहले दिखाया कि साम्राज्यवाद की मुख्य विशेषताएं हैं 1) एकाधिकारी पूंजी का विकास, 2) बैंक पूंजी और औद्योगिक पूंजी के सम्मिश्रण से वित्तीय पूंजी का जन्म, 3) माल के अलावा पिछड़े हुए देशों में वित्तीय पूँजी का निर्यात, 4) विश्व के बाजार हड़पने के उद्देश्य से विभिन्न साम्राज्यवादी एकाधिकारी पूँजीपतियों की एसोसियेशन उभरकर आना जिन्होंने वर्तमान में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का रूप ले लिया है, 5)सारी दुनिया को लूटने के लिए बड़े-बड़े पूँजीपतियों के बीच दुनिया का बंटवारा कर लेना।

लेनिन ने दिखाया कि लूट के बाजारों को हथियाने, दोबारा कब्जा करने के लिए ही साम्राज्यवाद विश्व युद्धों सहित तमाम युद्ध छेड़ता है। उन्होंने यह भी कहा है कि वित्तीय पूँजी इतनी ताकतवर और महत्वपूर्ण शक्ति हो गई है कि यह राजनीतिक तौर पर पूर्ण स्वतंत्र एक देश के समूचे आर्थिक और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को भी नियंत्रित कर सकती है। उन्होंने साम्राज्यवाद के शुरूआती स्तर में अभिव्यक्त एक और विशेषता भी दिखायी थी। वह है साम्राज्यवादी मुनाफा कमाने के लिए औपनिवेशिक, अर्ध-औपनिवेशिक और पिछड़े पूँजीवादी देशों में पूँजी निवेश करके उद्योग लगाते थे। इसके साथ में उन्होंने ध्यान दिलाया था कि उद्योगों में सीधे पूंजी निवेश करने में अगर नुकसान होता है, तो उसके लिए एक और रास्ता वे ले रहे हैं, वह है सीधे पूँजी निवेश न करके दूसरों को लोन या कर्ज देकर सूदखोरी का कारोबार करना और शेयर बाजार में सट्टेबाजी करना। उन्होंने पाया कि सूदखोरी के कारोबार में रिश्क या जोखिम काफी कम होता है। लेनिन ने इसे ब्राण्डिड किया किरायाजीवी या सूदखोर वित्तीय पूँजी के रूप में जो भारी ब्याज पर कर्ज देने के धंधे में लिप्त है और इस तरह कम से कम जोखिम उठाकर अच्छा-खासा मुनाफा कमा रही है। लेनिन ने उस समय में पूंजी की यह विशेषता जितनी दिखायी थी, आज के दिनों में तो वह और भी कई गुना बढ़ गयी है।

उन्होंने दिखाया है कि साम्राज्यवाद के पूर्ववर्ती स्तर में पूंजीवाद की विशेषता थी लोकतंत्र और व्यक्ति स्वतंत्रता पर जोर देना, अब उसकी बजाय साम्राज्यवादी स्तर में विशेषता हो गयी है अफसरशाही और सामरिक जंगखोरी।

द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय का अधोपतन

प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से पहलें लेनिन के साथ द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय के दूसरे-दूसरे नेताओं का तीव्र मतभेद हो गया था, युद्ध शुरू होने पर साम्राज्यवादी देशों के मजदूर वर्ग की भूमिका क्या होगी इस प्रश्न को लेकर। लेनिन ने कहा था कि अपने-अपने देश के साम्राज्यवादी शासकों के स्वार्थ में एक देश के मजदूर दूसरे देश के मजदूरों के खिलाफ बन्दूक नहीं चला सकते। उनका फर्ज होगा साम्राज्यवादी युद्ध की मुखालफत करना और युद्ध के मौके का फायदा उठाकर अपने-अपने देश के शासकों के खिलाफ गृह युद्ध छेड़ते हुए सर्वहारा क्रान्ति को कामयाब करना। हालांकि द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय के नेताओं ने लेनिन के विचारों का मौखिक तौर पर समर्थन किया और उनके प्रस्ताव पर सहमत हुए, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद उन्होंने पल्टी मारी और वे अपने-अपने देश के साम्राज्यवादी शासकों के समर्थन में जा खड़े हुए। लेनिन ने इस भूमिका को अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के साथ गद्दारी करार दिया और प्रथम विश्वयुद्ध के मौके का फायदा उठाकर अपने देश में क्रान्ति सफल की। इस प्रकार उन्होंने अपने नजरिये की सटीकता सिद्ध की। इसके अलावा, पिछड़े हुए देश रूस में समाजवादी क्रान्ति और सर्वहारा अधिनायकत्व कायम करने को लेकर भी लेनिन के साथ द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय के नेताओं का तीव्र मतभेद हुआ। इन सब कारणों से द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय

(शेष पृष्ठ 4 पर)

शहीद खुदीराम बोस की एक आदमकद प्रतिमा की स्थापना

घाटशिला (झारखण्ड) : विगत 11 अगस्त को घाटशिला स्टडी सेंटर स्थित शिवदास घोष मेमोरियल पार्क में अमर शहीद खुदीराम बोस की एक आदमकद प्रतिमा स्थापित की गयी। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के सिलसिले में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। घाटशिला और इसके आस-पास के इलाके से सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए इस कार्यक्रम को देखने के लिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विशिस्ट शिक्षाविद श्री मनीन्द्र नाथ पालित ने की।

प्रतिमा अनावरण करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी स्थानीय मारवाड़ी उच्च विद्यालय की पूर्व प्रधानाध्यापिका श्रीमती बियाट्रिस कश्यप। एक क्रांतिकारी गीत के बाद जैसे ही प्रतिमा के सामने से पर्दा हटाया जाने लगा, संगीत मंडली की ओर से 'एक बार विदाय दे मां, घुरे आसि...' गीत प्रस्तुत किया गया। उपस्थित सभी लोग इससे भाव विभोर हो गये।

मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमिटी के झारखंड राज्य सचिव कॉमरेड सुमित राय। उन्होंने विस्तार से खुदीराम बोस के जीवन-संघर्ष, विचारों और आज के सन्दर्भ में उनकी प्रासंगिकता पर बात रखी। इस अवसर पर बांग्लादेश से क्रांतिकारी छात्र संगठन 'समाजवादी छात्र फ्रंट' के नेतृत्वकारी साथी भी आए थे। संगठन की अध्यक्ष नाइमा खालेद मोनिका ने भी अपने विचार प्रस्तुत किये।

सभा का संचालन ऑल इंडिया डीएसओ के सर्वभारतीय अध्यक्ष कॉमरेड कमल सांई ने किया। इस मौके पर उपस्थित थे शिवदास घोष मेमोरियल ट्रस्ट के कर्णधार कॉमरेड रंजीत धर, स्वपन घोष आदि।

कार्यक्रम के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। कॉमसोमॉल की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

महान नवम्बर क्रान्ति शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कारखाना मजदूरों का जुलूस

समालखा: शहर में जुलूस निकालते हुए कारखाना मजदूर

समालखा (हरियाणा) : महान नवम्बर क्रान्ति शताब्दी वर्ष के अवसर पर ऑल इण्डिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) से सम्बद्ध कारखाना मजदूर यूनियन द्वारा पानीपत जिला के समालखा में 1 सितम्बर को जुलूस निकाला गया। श्रमिक हाथों में लाल झण्डे-बैनर लेकर 'मजदूर एकता जिन्दाबाद!', 'समाजवाद जिन्दाबाद!', 'पूंजीवाद का नाश हो!' के नारे लगा रहे थे। जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ हरिजन चौपाल में पहुंच कर जनसभा में तब्दील हो गया।

सभा की अध्यक्षता एआईयूटीयूसी के प्रांतीय सचिव कॉ. हरिप्रकाश ने की। मंच संचालन कारखाना मजदूर यूनियन के नेता कॉ. महेन्द्र सिंह ने किया।

एसयूसीआई(सी) के सोनीपत जिला सचिव कॉमरेड ईश्वर सिंह राठी ने भी सभा को सम्बोधित किया।

इस अवसर पर शेर सिंह, जीत, दलबीर, सुरेश, राजबीर, राममेहर, सोनालाल आदि साथी भी मौजूद थे।

विरोध दिवस...

(पृष्ठ 1 का शेष)

केजरीवाल के आवास से दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल के कार्यालय तक जुलूस निकाला गया। इसमें दिल्ली के विभिन्न इलाकों से आई महिलाओं ने हिस्सा लिया और महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ आवाज बुलंद की। उपराज्यपाल कार्यालय पर जाकर जुलूस एक सभा में तब्दील हो गया। सभा को संगठन की दिल्ली राज्य सचिव श्रीमती रितु कौशिक, उपाध्यक्ष श्रीमती पुष्पा चमोली, श्रीमती नीतू खन्ना, सचिवमंडल सदस्यों श्रीमती आशा रानी, श्रीमती सीता सिंह, श्रीमती सुमन यादव, मीरा चौरसिया, संध्या विश्वकर्मा, मौसम कुमारी तथा श्रीमति शारदा दीक्षित ने संबोधित किया। अगले दिन श्री केजरीवाल ने संगठन के पंगठन के प्रतिनिधिमण्डल से बातचीत की।

वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं पर बढ़ते अन्याय-अत्याचारों ने आज गंभीर रूप ले लिया है। महिलाओं के अपहरण, तस्करी, छेड़छाड़, बलात्कार, गैंगरेप और हत्या, जैसे संगीन अपराध बढ़ रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या, इज्जत के नाम पर हत्याएं (ऑनर किलिंग), सैक्स टूरिज्म, देह व्यापार और कार्य-स्थलों पर यौन-शोषण व उत्पीड़न जैसी समस्याएं भी गंभीर रूप लेती जा रही हैं। इनके अलावा दहेज, दहेज-उत्पीड़न, दुल्हन-दहन जैसे अत्याचार किये जाते हैं। सरकार व प्रशासन इनकी रोकथाम करने में विफल हैं। टी. वी. चैनलों, पत्र-पत्रिकाओं, फिल्मों व सौंदर्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से अश्लीलता परोसी जा रही है। नारी देह को उपभोग की वस्तु की तरह दर्शाया जा रहा है। इससे अपराधों को बढ़ावा मिलता है। अपराध बढ़ने का एक प्रमुख कारण नशाखोरी भी है। फिर भी सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। अफवाहें फैलाकर और महिलाओं के मन में भय बैठाकर उनका ध्यान महंगाई-बेरोजगारी-सांस्कृतिक पतन आदि मुद्दों से नकली मुद्दों की ओर फेरा जा रहा है। अनेक मामलों में सरकारी मशीनरी महिलाओं को न्याय दिलाने के बजाय उल्टे दोषियों की ही तरफदारी करती है और खुद भी इस कमजोर तबके पर अन्याय-अत्याचार करती है। साम्प्रदायिक हमलों में भी महिलाओं पर बर्बर जुल्म किये जाते हैं।

वक्ताओं ने महिलाओं से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन को मजबूत करने के लिए आगे आएँ ताकि सरकार को महिलाओं और बच्चों पर बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान ए.आई.एम.एस.एस. की दिल्ली राज्य उपाध्यक्ष एडवोकेट कुसुम सिंह के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया।

दिल्ली: महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ एआईएमएसएस के बैनर तले सड़कों पर उतरी महिलाएं

सरायकेला-खरसांवा (झारखण्ड) : आदिवासी बहुल सरायकेला-खरसवा में जिला स्तर सहित सर्वत्र विरोध दिवस मनाया गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं की ओर से संगठन की जिला अध्यक्ष मालती देवी, उपाध्यक्ष विमला सिंह और कार्यालय सचिव अंजना भारती, दुखनी मांझी, अंजु सिन्हा, सुधा सिंहा, सावित्री गिरी, दुर्गावती देवी आदि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि पूर्ण

शराबबन्दी लागू हो, सरकारी शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द करो, महिलाओं को सुरक्षा की गारन्टी दो, हर तरह के महिला उत्पीड़न रोकने हेतु सख्त कदम उठाये जाएं।

विदित हो कि जहाँ पूरे दूश में समाज के हर तबके के द्वारा शराबबन्दी की आवाज उठ रही है, बिहार सहित 4 राज्यों में शराबबन्दी लागू है, जिसमें गुजरात, नागालैण्ड और मणिपुर भी है, वहां हमारे झारखण्ड राज्य द्वारा राजस्व के नाम पर शराब बिक्री का निर्णय पूर्ण रूप से जनविरोधी है। हम सभी जानते हैं कि समाज में जो भी आपराधिक घटनायें घट रही हैं, उसके लिए मुख्य रूप से शराब को जिम्मेदार पाया गया है। आदिवासी बहुल क्षेत्र सरायकेला-खरसावां जिले के ज्यादातर परिवार शराब के चलते बर्बाद हो रहे हैं। महिलाएं शराब के कारण उत्पीड़ित हो रही हैं। शराब के कारण कमाई का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो रहा है। इन सारी घटनाओं से रूबरू होने के बावजूद जनता के विरोध की परवाह किए बिना सरकारी शराब की दुकान खोलने का निर्णय जनविरोधी है।

त्रिपुरा : संगठन की त्रिपुरा राज्य कमेटी की ओर से अगरतला के ओरियंट चौराहे पर एक सभा की गई। राज्य अध्यक्ष कॉ. शिवानी दास, अपाध्यक्ष कॉ. शैफाली भौमिक, राज्य सचिव कॉ. शुल्का चक्रवर्ती ने वक्तव्य रखा।

आसाम : संगठन की राज्य कमेटी के तत्वावधान में गुवाहाटी में विक्षोभ सभा की गई। संगठन की राज्य अध्यक्ष ईना हुसैन ने सभा की अध्यक्षता की। सभा के मुख्य वक्ता एसयूसीआई(सी) की राज्य सचिव कॉ. चन्द्रलेखा दास थी।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

लेनिन और नवम्बर क्रान्ति

(पृष्ठ 2 का शेष)

को विश्वासघातक और संशोधनवादी करार देते हुए उन्होंने इससे अपना नाता तोड़ लिया।

एक कम्युनिस्ट पार्टी के गठन पर

लेनिन का एक असाधारण महत्वपूर्ण योगदान है कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह से निर्मित होगी यह नीति सिद्धान्त पेश करना। कॉमरेड शिवदास घोष ने जिसे लेनिनीय पद्धति कहा है और जिसको कॉमरेड शिवदास घोष ने और भी उन्नत और विकसित किया है। कॉमरेड शिवदास घोष ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'एसयूसीआई(सी) ही भारत में एकमात्र साम्यवादी पार्टी क्यों' में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। बारीकी से पढ़ने पर कॉमरेडों को इस बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। अपने देश में आरएसडीएलपी में रहते समय उस पार्टी में भी प्लेखानोव, मार्तोव, एक्स्लरोड आदि के साथ लेनिन का सैद्धान्तिक मतभेद हुआ था। ऐसे मुद्दों में एक अहम सवाल यह था कि एक कम्युनिस्ट पार्टी कैसे गठित होगी। इसको लेकर मतभेद हुआ था। लेनिन ने कहा कि वैचारिक संघर्ष चलाकर यूनिटी ऑफ आइडियाज (विचारों की एकता) पहले होनी चाहिए। इसकी व्याख्या करते हुए कॉमरेड शिवदास घोष ने इसे वैचारिक केन्द्रीयता कहा है। लेनिन ने कहा कि सिर्फ एक प्रस्ताव पास करके या कुछ घोषणाएं करके मजदूर वर्ग की पार्टी गठित नहीं की जा सकती। इस पार्टी के गठन के लक्ष्य से पहले हर क्षेत्र में वैचारिक एकता कायम करने के लिए वैचारिक संघर्ष करना होगा। इसके बाद सवाल उठा था कि पार्टी के मेम्बर कौन होंगे। लेनिन ने कहा था प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरी (पेशेवर क्रान्तिकारी) के सिवाय पार्टी का मेम्बर नहीं हो सकता। दूसरों का कहना था कि जो पार्टी के नीति-सिद्धान्त को मानता है, पार्टी के वक्तव्य को मानता है वही पार्टी का मेम्बर हो सकता है। लेनिन ने कहा था–नहीं, ऐसा होने से पार्टी में जो कोई भी आदमी मेम्बर हो जाएगा, इस तरह मजदूर वर्ग की क्रान्तिकारी पार्टी नहीं चल सकती। यह जांच-पड़ताल करना जरूरी है कि कोई पार्टी के नियम-सिद्धान्त, अनुशासन मानकर किसी संगठन के तहत काम कर रहा है या नहीं। मेम्बर बनने के लिए यही विचारणीय होगा। नतीजतन, आरएसडीएलपी दो धड़ों में बंट गई–मेन्शेविक और बोल्शेविक। बाद में 1912 में बोल्शेविक पार्टी विधिवत ढंग से गठित हुई। फलस्वरूप कम्युनिस्ट पार्टी कैसे गठित करनी होगी, सर्वहारा जनतंत्र और केन्द्रीयता के मिश्रण के जरिए किस तरह जनवादी केन्द्रीयता निर्मित होगी, हर स्तर पर पार्टी कमेटियां कैसे गठित होंगी और इनका आपसी सम्बन्ध क्या होगा, अथोरिटी को मानकर किस तरह अनुशासनबद्ध होकर काम करना होगा -विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन में इन शिक्षाओं को मार्क्स-एंगेल्स के उत्तराधिकारी के तौर पर लेनिन ही विस्तार से लाये थे।

सर्वहारा के अधिनायकत्व पर

सर्वहारा जनतंत्र और बुर्जुआ जनतंत्र में क्या फर्क है यह भी लेनिन ने ही दिखाया है। डिक्टेटरशिप आफ दि प्रोलेटेरिएट (सर्वहारा का अधिनायकत्व) के सवाल को लेकर भी बहस हुई थी। मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद से साम्यवाद में पहुंचने का संक्रमणकाल है सर्वहारा का अधिनायकत्व। लेनिन जब इसको प्रयोग करने लगे तो सभी ने कहा कि तुम जनतंत्र की हत्या कर रहे हो। लेनिन ने कहा कि जिस जनतंत्र की बात तुम कर रहे हो वह है बुर्जुआ डिक्टेटरशिप अर्थात् बुर्जुआ वर्ग के पक्ष में वह जनतंत्र है परन्तु मजदूर वर्ग के खिलाफ वह डिक्टेटरशिप होती है। जबकि समाजवाद होता है मजदूर वर्ग के स्वार्थ में जनतंत्र और बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ डिक्टेटरशिप। मार्क्स के इससे सम्बन्धित सिद्धान्त और धारणाओं को भी लेनिन ने विभिन्न पहलुओं से काफी विकसित किया है। शान्तिपूर्ण तरीके से क्रान्ति नहीं हो सकती यह बात मार्क्स ने ही कही थी। मजदूर वर्ग को बुर्जुआ राजसत्ता भी तोड़नी होगी, पेरिस कम्यून के पतन के तुर्जुबे से मार्क्स यह शिक्षा पेश कर गये थे।

निरंतर विकासमान है मार्क्सवादी विज्ञान

एक अन्य क्षेत्र में भी लेनिन की बड़ी भारी ऐतिहासिक भूमिका है। मार्क्स-एंगेल्स के परवर्ती दौर में जो बुर्जुआ चिंतनकार नये सिरे से मार्क्सवाद पर हमला कर रहे थे, तरह-तरह से विज्ञान की गलत व्याख्या कर रहे थे। इन हमलों के खिलाफ मार्क्सवाद की रक्षा करना बहुत जरूरी था। लेनिन ने ऐसा ही किया और इसी के क्रम में मार्क्सवादी सिद्धान्त को भी उन्होंने विकसित किया। उन्हें रूस की सरजमीं पर तथाकथित मार्क्सवादी सिद्धान्तकारों बाजारोव, बोग्दानोव, लुनाचारस्की सरीखे और उनके विदेशी समर्थकों के खिलाफ यह वैचारिक संघर्ष चलाना पड़ा। लेनिन ने मार्क्सवाद को जड़सूत्र (डोग्मा) के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने मार्क्सवाद को रचनात्मक और विकासमान विज्ञान के तौर पर क्रिया के मार्गदर्शक के तौर पर ग्रहण किया था। इस बारे में उनकी विख्यात युक्ति है, "हम मार्क्सवाद के सिद्धान्त को 'कम्पलीटिड (सम्पूर्ण) और अनुल्लंघनीय नहीं मानते, बल्कि इसके उलट हम समझते हैं कि इसने विज्ञान की मूल आधारशिला रखी है जिसे सोशलिस्टों को चलायमान जीवन के साथ सामन्जस्य रखते हुए और हर क्षेत्र में और भी आगे ले जाना होगा।"(रोचाया गजट के लिए लेख, कलेक्टिड वर्क्स, वोल्यूम 4, पृ. 211-12) यही काम लेनिन ने मार्क्स-एंगेल्स के बाद के दौर में साम्राज्यवादी स्तर में किया था। इसी वजह से महान लेनिन के सुयोग्य शिष्य महान स्तालिन ने कहा था, ''लेनिनवाद है साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रान्ति के युग का मार्क्सवाद।''(लेनिनवाद का आधार) 'लेनिनवाद'–यह संज्ञा स्तालिन ने ही पहले पहल दी थी।

सांइस जिस तरह विकसित हो रही है, मार्क्सवाद भी उसी तरह सांइटिफिक फिलोसोफी होने के नाते विकसित हो रहा है। यह दो तरह से विकसित हो रहा है। एक है मार्क्सवाद के तीन मूलभूत सार्वभौम सिद्धान्तों अर्थात् (1) विरोधी शक्तियों की एकता और संघर्ष, (2) मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन और विपरीत क्रम में, (3) निषेध का निषेध–की समझदारी का निरंतर विकास और समृद्ध होते जाना। जैसे विज्ञान में न्यूटन ने वस्तु की गति के नियम खोजे थे। विज्ञान में ये नियम आज भी सही हैं। लेकिन वस्तु की गति की धारणा न्यूटन के समय के बाद में हुए और भी नये-नये आविष्कारों की रोशनी में विकसित हुई है। इसी तरह मार्क्सवाद के श्री प्रींसिपल्स की धारणा भी उसी तरह विकसित हो रही है और विज्ञान तथा ज्ञान जगत के क्षेत्र में नई-नई उन्नतियों के साथ समृद्ध हो रही है। इस सम्बन्ध में दूसरा डेवल्पमेंट है मार्क्सवादी विज्ञान का इस्तेमाल करते हुए विशेष परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थिति में क्रान्ति की रणनीति और रणकौशल निर्धारित करना। फिर यह परिस्थिति भी जैसे-जैसे बुनियादी तौर पर बदल रही है उसके मुताबिक नयी क्रान्तिकारी लाइन निर्धारित करना, उत्पन्न हुई नयी-नयी समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में नये ढंग से रोशनी डालना। इसीलिए लेनिन ने बदली हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में सर्वहारा क्रान्ति की लाइन तय की सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि यह जनरल लाइन हूबहू सभी देशों के मामलों में एक ही तरह से लागू नहीं होती है। उन्होंने कहा, ''हमारा मानना है कि रूसी समाजवादियों के लिए विशेष तौर पर जरूरी है कि मार्क्स के सिद्धांत की एक स्वतंत्र व्याख्या की जाये। यह थ्यूरी केवल जनरल गाइडिंग प्रींसिपल तय करती है। वह इंग्लैण्ड में फ्रांस से भिन्न तरह से, फ्रांस में जर्मनी से अलग ढंग से, जर्मनी में रूस से भिन्न तरीके से लागू होगी।'' (वही) इसलिए देखा जा सकता है कि लेनिन ने उन समस्याओं का मुकाबला किया जो मार्क्स के समय में पैदा ही नहीं हुई थी। लेनिन ने नई-नई समस्याओं के समाधान पर मार्गदर्शन प्रदान करने के क्रम में मार्क्सवाद को समृद्ध किया और मार्क्सवाद को नये स्तर पर बुलन्द किया। लेनिन के बाद स्तालिन, माओ-त्से-तुंग, शिवदास घोष ने मार्क्सवाद को विकसित और समृद्ध किया है।

क्रान्ति संगठित करने के बारे में

रूस में क्रान्ति संगठित करने के मामले में भी लेनिन की प्रतिभा ने किस तरह काम किया था वह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक तरफ जैसे वैचारिक संघर्ष चलाते हुए बोल्शेविक पार्टी निर्मित हुई थी वहीं दूसरी तरफ रूस में काफी ताकत लेकर समझौतापरस्त मेन्शेविक पार्टी थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी। इनको भी लगातार बेनकाब करते हुए मजदूर वर्ग, गरीब किसान और जनता से अलग-थलग किया। लेकिन नवम्बर क्रान्ति इस तरह नहीं हुई कि लम्बे समय तक गांव-गांव में, शहर-शहर में, इलाके-इलाके में पार्टी संगठन निर्माण किया हो, विभिन्न जायज मांगों पर वर्ग संघर्ष और जनान्दोलन गठित किया हो, विचारधारा का प्रचार किया हो, कमेटियां गठित की हों–जैसेकि हमें सापेक्षत: विकसित पूंजीवादी देश में क्रान्ति संगठित करनी पड़ रही है। यह ठीक है कि देश में लेनिन के क्रान्तिकारी विचारों का प्रभाव व्यापक तौर पर पड़ा था, पहले वाली आरएसडीएलपी के भी ज्यादातर भाग ने लेनिन का ही समर्थन किया था।

इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जारशाही रूस में लम्बे अर्से की संसदीय राजनीति करने का मौका नहीं था। ड्यूमा (संसद) लोगों के दबाव के चलते कभी-कभार गठित की जाती थी। लेनिन प्रत्येक ड्यूमा अस्थाई प्रकृति की होती थी और सीमित मताधिकार व अलोकतांत्रिक संविधान के आधार पर गठित की जाती थी। इसलिए लोगों के अन्दर संसदीय मोह पैदा करने का बहुत कम मौका था, यह अन्य विकसित साम्राज्यवादी- पूँजीवादी देशों की तरह नहीं था। रूस में मजदूर वर्ग को घूस नहीं दी गई थी। वह भ्रष्ट नहीं हुआ था। आर्थिक अवसरवाद के बहाव में भी वह नहीं बह गया था जिस हद तक साम्राज्यवादी पूँजी अन्य पश्चिमी देशों में कर सकी थी। इसलिए रूसी मजदूर सापेक्ष तौर पर जुझारू थे। इसके अलावा, तत्कालीन रूस में धार्मिक मूल्यबोध पूरी तरह निशेषित नहीं हुए थे और बुर्जुआ मानवतावादी मूल्यों का गहरा प्रभाव था। रूस को उस समय गहन नैतिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा जैसा कि हमारे देश सहित तमाम साम्राज्यवादी-पूँजीवादी देशों को आज करना पड़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में, विभिन्न आर्थिक और अन्य मांगों को लेकर तब रूस में औद्योगिक हड़तालों का सिलसिला शुरू हो गया था और 1905 में क्रान्ति की पूर्व वेला पर बोल्शेविकों के प्रयासों की वजह से इन तमाम हड़तालों को राजनैतिक हड़तालों में बदल दिया गया था। क्रान्तिकारी अभ्युत्थान में सशस्त्र सेनाएं और नौसेनिक बेड़े भी शामिल हो गए थे। राजनैतिक शक्ति के हथियार के तौर पर मजदूरों और सैनिकों तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों के बीच भी स्वत:स्फूर्त ढंग से सोवियतें विकसित हो गई थी। हालांकि क्रान्ति को सफल बनाने के लिए बोल्शेविकों के पास ज्यादा राजनैतिक या सांगठनिक शक्ति नहीं थी, फिर भी 1905 के अभ्युत्थान के समय उनकी भूमिका से निस्संदेह साफ हो गया था कि वे उस समय सर्वाधिक भरोमंद ताकत थे। लेनिन ने 1905 की इस क्रान्ति को भविष्य की नवम्बर क्रान्ति की 'ड्रेस रिहर्सल' बताया था और कहा था कि अगर 1905 में क्रान्ति का प्रयास नहीं किया गया होता तो 1917 में नवम्बर क्रान्ति कदापि नहीं हो सकती थी।

बोल्शेविक शब्द का अर्थ है बहुसंख्यक और मेन्शेविक शब्द का अर्थ है अल्पसंख्यक। इसलिए दूसरे सोशल डेमोक्रेटों की तुलना में बोल्शेविक पार्टी शक्तिशाली थी। क्रान्ति-पूर्व रूस के हालात भी हमारे देश के आजादी पूर्व हालात जैसे ही थे। रूस में पूँजीवाद उस तरह से नहीं उभर कर आया था। असल में, रूस में पूँजीवाद का विकास हमारे आजादी आन्दोलन के दौरान भारतीय पूँजीवाद के विकास के मुकाबले कमजोर था। रूस में जारतंत्र था, मतलब कृषि दासता के तहत सामंतवाद के नुमाइन्दे के तौर पर लार्ड जार का शासन। कृषि में व्यापक तौर पर सामंतवाद मतलब भूस्वामी-भूदास सम्बन्ध था। सिर्फ कुछ ही मिल-कारखानें स्थापित हुए थे–यही थी स्थिति। फिर जार के सहयोग के आधार पर विदेशी साम्राज्यवादी पूंजी भी कुछ-कुछ काम कर रही थी। अत: रूस एक बुर्जुआ जनवादी क्रान्ति के स्तर में ही था। उस समय के हालात ऐसे ही थे।

बुर्जुआ जनवादी क्रान्ति होती है निजी मालिकाना कायम करने की क्रान्ति। सामंतवाद मतलब राजा, सामंत

(शेष पृष्ठ 6 पर)

बिजली दर वृद्धि व गोरखपुर में हुए मासूमों की मौत के जघन्य कांड के खिलाफ उठी आवाज

मुरादाबाद (उ.प्र.) : सरकार द्वारा बिजली दरों में प्रस्तावित बेतहाशा वृद्धि, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से मासूमों की मौतों के खिलाफ एसयूसीआई (सी) पार्टी के प्रदेशव्यापी विरोध दिवस के क्रम में 18 अगस्त को मुरादाबाद जिला यूनिट की तरफ से जिला सचिव विजयपाल सिंह के नेतृत्व में जोरदार जन प्रदर्शन किया गया तथा महामहिम राज्यपाल, उ.प्र. को सम्बोधित ज्ञापन मुरादाबाद जिला अधिकारी को सौंपा गया। इसमें, मांग की गई :

1. विद्युत दरों में प्रस्तावित बेहतहाश मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाए तथा आम उपभोक्ताओं व किसानों को सस्ती दरों पर 24 घण्टे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
2. गोरखपुर के बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की न्यायिक जाँच करायी जाए।
3. दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमें दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए।
4. पीड़ित परिवारों को कम से कम 20-20 लाख का मुआवजा दिया जाए।
5. पूरे प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाया जाए।

पार्टी के पदाधिकारी व आम जन टाउन हाल पर इकट्ठा हुए तथा जुलूस के रूप में नारे लगाते हुए कचहरी पहुँचकर जुलूस सभा में बदल गया।

सभा को सम्बोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा विद्युत दरों में प्रस्तावित वृद्धि किसानों व आम उपभेक्ताओं की कमर तोड़ देगी जो पहले से ही महंगाई व फसल का उचित मूल्य न मिलने से बदहाल हैं। सरकार का रवैया घोर जनविरोधी है व किसान विरोधी है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। गोरखपुर में किस प्रकार कमीशन खोरी व उॅपर से नीचे तक घोर भ्रष्टाचार के कारण ऑक्सीजन की कमी से मासूमों को मार दिया गया तथा कार्यवाही करने की बजाय सरकार झूठ बोल रही है। मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।

प्रदर्शन में इस्लाम अली, रामेश्वरी देवी, नवाब अली, माया राजपूत, रेजन नंदा, सुरेश पाल, रूबी खान, राकेश शर्मा, मो. गौरी, मो. हसल, मो. इरशद, नंदराम, विनोद विग एडवोकेट, धर्मपाल सिंह आदि उपस्थित थे।

जे.पी. नगर (उ.प्र.) : बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मासूमों की मौत के दर्दनाक काण्ड में लगभग 75 बच्चे मारे गये, इस घटना के खिलाफ 18 अगस्त को एसयूसीआई (सी) की जिला अमरोहा यूनिट द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी अमरोहा की मार्फत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने इस जघन्य अपराध की घोर निन्दा की। ज्ञापन में मांग की गई कि विद्युत दरों में प्रस्तावित बेहतहाशा मूल्य वृद्धि वापस ली जाए तथा आम उपभोक्ताओं व किसानों को सस्ती दरों पर 24 घण्टे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, गोरखपुर के बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की न्यायीक जाँच करायी जाए, दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमें दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए।

प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश में बिजली की दरों में हुई बेतहाशा वृद्धि का भी कड़ा विरोध किया।

महान नवम्बर क्रान्ति शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में युवा कैम्प आयोजित

बोकारो (झारखण्ड) : 27 अगस्त को महान नवम्बर क्रान्ति शताब्दी वर्ष के अवसर पर बेरोजगारी, अपसंस्कृति, नशाखोरी तथा जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की झारखण्ड कमेटी के बैनर तले राज्य स्तरीय एक दिवसीय युवा कैम्प का आयोजन बोकारो जिले में किया गया। कैम्प की शुरूआत झंडा फहराने तथा शहीद बेदी पर पुष्पार्पण के साथ हुई। एआईडीवाईओ झारखण्ड के केन्द्रीय प्रभारी अखिल भारतीय सचिव मण्डल सदस्य कॉमरेड उमा शंकर ने झण्डा फहराया। कैम्प की अध्यक्षता झारखण्ड संगठन की राज्य अध्यक्षा कॉमरेड गीता शर्मा ने की। कैम्प के मुख्य अतिथि के तौर पर एसयूसीआई (सी) के झारखण्ड के राज्य सचिव कॉमरेड रॉबिन समाजपति तथा मुख्य वक्ता के तौर पर एआईडीवाईओ झारखण्ड के केन्द्रीय प्रभारी अखिल भारतीय सचिव मण्डल सदस्य कॉमरेड उमा शंकर उपस्थित थे। मंच पर एआईडीवाईओ अखिल भारतीय कार्यालय सचिव कॉमरेड ज्ञानोतोश प्रमाणिक एसयूसीआई (सी) के झारखण्ड कमेटी सदस्य कॉमरेड आर.एस. शर्मा तथा एआईडीवाईओ के पूर्व अखिल भारतीय उपाध्यक्ष कॉमरेड दीपक कुमार भी उपस्थित थे। कैम्प में राज्य के विभिन्न जिलों से करीब 60 की संख्या में प्रतिनिध शामिल हुए। सर्वप्रथम कैम्प की सभापति ने अपना अध्यक्षीय भाषण पेश किया। उसके उपरांत कैप में प्रतिनिधित्व कर रहे संजय, विशाल कुमार, उदय तंतुबाई, विजय कुमार, भुजंग मछुआ, मानसी कुमारी, देवी मुखी, रूपा सरकार आदि ने वर्तमान में युवाओं की स्थिति पर अपना व्यक्तव्य रखा। इसके उपरान्त मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि ने

बारीकी से महान नवम्बर क्रान्ति की सीखों पर रोशनी डाली।

उन्होंने बताया कि कैसे 100 साल पहले मानव इतिहास में रूस में पहली बार समाजवाद की स्थापना हुई। मुख्य अतिथि कॉमरेड रॉबिन समाजपति तथा एआईडीवाईओ अखिल भारतीय कार्यालय सचिव कॉ ज्ञानोतोश प्रमाणिक ने कोलकाता में आयोजित होने वाले समारोह को सफल बनाने के लिए तत्काल युवाओं के बीच महान नवम्बर रूसी समाजवादी क्रान्ति का संदेश पहुंचाने की अपील की। कैम्प में संगीत मण्डली ने कई क्रान्तिकारी तथा जनवादी गीत प्रस्तुत किए। कैम्प का संचालन संगठन के राज्य सचिव कॉ. संशात सरकार ने किया।

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एआईएमएसएस

24 अगस्त 2017 को जारी एक बयान में एआईएमएसएस ने एक साथ तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए माना कि सभी धर्म महिला को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं और महिलाएं इस देश में सभी अंधविश्वासों और कुसंस्कारों का सबसे बुरी शिकार होती हैं। इसलिए महज कानून लागू होने से ही महिलाओं की स्थिति अपने आप नहीं बदल जाती है। लिहाजा दकियानूसी, गये गुजरे और प्रतिक्रियावादी दस्तूरों और रीति-रिवाजों और साथ ही पुरुष प्रधानता की जंजीरों से महिलाओं को मुक्त करने के लिए एक जोरदार सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन गठित करना निहायत जरूरी है।

तेलंगाना सरकार के जनविरोधी कदम के खिलाफ

संयुक्त वामपंथी आन्दोलन

दिल्ली : धरना चौक पर विरोध प्रदर्शन और आन्दोलन के कार्यक्रम करने पर मनमानी रोक लगाने के टीआरएस-नीत तेलंगाना सरकार के घोर अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ एसयूसीआई(सी) सहित वामदलों को लेकर बनी धरना परिरक्षण कमेटी की ओर से गत दिनों यहां जंतर मंतर पर विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। यह चौक अब तक ऐसे सब जलसे-जुलूसों का स्थल रहा है। इससे पहले जुलाई, 2017 में हैदराबाद में विरोध का कार्यक्रम आयोजित किया गया और राज्य के राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर मांग की गई कि तेलंगाना में लोकतंत्र की रक्षा की जाए। लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। इसलिए तेलंगाना सरकार के इस घोर अलोकतांत्रिक कदम की तरफ केन्द्र सरकार का ध्यान दिलाने के लिए दिल्ली में ये कार्यक्रम किया गया।

उत्तराखण्ड में एआईडीएसओ का सम्मेलन

श्रीनगर-गढ़वाल : शहीद खुदीराम बोस का शहीदी दिवस मनाने के साथ ही उत्तराखण्ड के श्रीनगर-गढ़वाल के नगरपालिका हाल में 12 अगस्त को श्रीनगर-गढ़वाल दूसरा छात्र सम्मेलन आयोजिक किया गया। एआईडीएसओ के महासचिव कॉमरेड अशोक मिश्रा ने मुख्य वक्ता के तौर पर अपने भाषण में शहीद खुदीराम बोस के जीवन-संघर्ष पर रोशनी डाली और शिक्षा-विरोधी नीतियों के खिलाफ छात्र आन्दोलन चलाने पर जोर दिया। सम्मेलन में जाने-माने ट्रेड यूनियन नेता श्री पी.बी. डोबवाल और एआईडीएसओ के उपाध्यक्ष कॉ. भास्करानंद भी मौजूद थे।

सम्मेलन की अध्यक्षता संगठन के श्रीनगर-गढ़वाल के नगर अध्यक्ष कॉमरेड मोहित नेगी ने की। एक 21 सदस्यीय मजबूत नगर एआईडीएसओ कमेटी गठित की गई जिसके अध्यक्ष कॉमरेड रेशमा, उपाध्यक्ष कॉमरेड कुसुम पाण्डेय, सचिव कॉ. प्रवीण भण्डारी चुने गए। एआईडीएसओ के उपाध्यक्ष कॉमरेड मुकेश सेमवाल ने 5 सदस्यीय राज्य स्तरीय को-ऑर्डिनेशन कमेटी का एलान किया जिसके संयोजक कॉमरेड मोहित नेगी हैं।

झारखण्ड में जनआन्दोलन की महत्वपूर्ण जीत

रांची : झारखण्ड राज्य के आदिवासी मौजूदा 1908 के छोटा नागपुर टीनेन्सी एक्ट व 1949 के संथाल परगना टीनेन्सी एक्ट (सीएनटी-एसपीटी एक्ट) की वजह से अपने पुरखों की जमीन को भूमाफिया से बचाने में समर्थ हुए थे। लेकिन जब बीजेपी राज्य में सत्ता में आई तो परिदृश्य बदल गया और जमीन हड़पने वाली शार्कों के हित में इन कानूनों में संशोधन की कोशिशें शुरू की ताकि उनके लिए आदिवासियों की जमीन हड़पना आसान हो सके। बड़े कारपोरेटों व इजारेदार घराने का वर्ग स्वार्थ साधने के लिए बीजेपी सरकार ने इन कानूनों को बदलने के लिए प्रस्ताव के रूप में दस्तावेजों का पुलिंदा राज्यपाल के पास भेजा। लेकिन इसके खिलाफ एसयूसीआई(सी) ने 192 अन्य संगठनों के साथ मिल कर मुहीम छेड़ी। ज्ञापन सौंप कर सीएनटी-एसपीटी एक्ट में प्रस्तावित संशोधन न करने की मांग की। आन्दोलन के दबाव में सरकार 9 अगस्त को एलान करने पर मजबूर हुई कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट में प्रस्तावित संशोधन वापस ले रही है। इस महत्वपूर्ण जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सही नेतृत्व में सतत संयुक्त जन आन्दोलन इन्साफ की मांग के लिए साकार को झुका सकता है।

लेनिन और नवम्बर क्रान्ति

(पृष्ठ 4 का शेष)

प्रभु के अलावा और कोई सम्पत्ति का मालिक नहीं हो सकता था, भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर केवल वही मालिक होंगे। मर्कन्टाइल केपिटल जब इन्डस्ट्रीयल केपिटल में रूपांतरित हुई तब निजी मालिकाने का नारा उठाया, कुटीर उद्योगों को खत्म करके बड़े उद्योग लगाने होंगे, और भूदासों को मुक्त करके स्वतंत्र मजदूर होने का मौका देना होगा–ये सब नारे आये थे। आर्थिक नजरिये से ये सब मांगें उस समय प्रगतिशील थी, इनको आधार करके सभी व्यक्तियों को अधिकार है कि वे सम्पत्ति के मालिक हो सकते हैं। जनवादी मांग के तौर पर उभर कर आ गया, राइट टू हेव प्रोपर्टी (सम्पत्ति रखने का अधिकार) जो भारत के संविधान में भी है–इसे बुर्जुआ ही लाया है। पूँजीवाद में सम्पत्ति रखने का अधिकार हर व्यक्ति को है, ऐसा अधिकार सामंतवाद में नहीं था। इसी के आधार पर व्यक्ति स्वतंत्रता की धारणा आयी। इसी से आयी व्यक्ति की चिंतन करने की आजादी, मत प्रकट करने की आजादी, प्रतिवाद करने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, नारी स्वाधीनता, राजतंत्र की बजाय प्रजातंत्र या संसदीय जनतंत्र की स्थापना–ये सब अधिकार आये। मूलत: निजी मालिकाने की जरूरत के आधार पर ही ये सब आया था। इतिहास के उस स्तर पर बुर्जुआ जनवादी क्रान्ति प्रगतिशील थी। फ्रांस की क्रान्ति, इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति, जर्मनी का किसान युद्ध ये सब प्रगतिशील बुर्जुआ क्रान्तियां थी। इसी समय तो स्वतंत्रता-समानता-भाईचारे का नारा बुलन्द हुआ था। इसी प्रकार लोकतंत्र कायम करने, सरकारें बनाने का नारा, 'बाई दि पीपल-फॉर दि पीपल-ऑफ दि पीपल' का नारा आया था। व्यक्ति का अधिकार चाहिए–इसने लोगों को एक नयी चेतना दी, अधिकार बोध दिया। अत: उस समय व्यक्ति-स्वतंत्रता ने एक प्रगतिशील आकांक्षा को अभिव्यक्त किया था। हमारे देश के आजादी आन्दोलन के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, जिन्होंने जान कुर्बान की, उन में से कोई भी तो सर्वहारा क्रान्तिकारी नहीं था। बुर्जुआ मायने में ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता उनका दार्शनिक आधार था। क्योंकि आजादी आन्दोलन चरित्र में ही साम्राज्यवाद-विरोधी था–बुर्जुआ जनतंत्र कायम करने का एक आन्दोलन। सामंतवाद के खिलाफ भी लड़ाई करने की जरूरत थी हालांकि आजादी आन्दोलन के समझौतापरस्त नेतृत्व ने वह नारा बुलन्द नहीं किया। खैर जो भी हो, साम्राज्यवाद-विरोधी लड़ाई भी बुर्जुआ जनवादी क्रान्ति की लड़ाई ही थी। आजादी हासिल करने के मूल लक्ष्य को आधार करके हमारे देश में जो नेता कार्यकर्ता आये थे उनमें भी व्यक्ति का अधिकार, व्यक्ति की आजादी कायम करने की आकांक्षा काम कर रही थी।

एक सच्चा कम्युनिस्ट कैसे बना जाये इसकी समृद्ध धारणा

रूस में भी जब नवम्बर क्रान्ति से पहले फरवरी क्रान्ति हुई, मूलत: जनता की भी मांग थी व्यक्ति स्वाधीनता का अधिकार हासिल करना। बोल्शेविक पार्टी का नारा भी था व्यक्ति स्वाधीनता का अधिकार हासिल करना। यह बात कॉमरेडों के लिए खूब गौरतलब है। शरतचन्द्र के उपन्यास 'पथ के दावेदार' में है अपूर्व जब रामदास तलवरकर से कहता है, ''तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारे तो बाल-बच्चे हैं, तुम क्यों इस क्रान्तिकारी आन्दोलन में जुड़ गये?'' रामदास कहता है, ''बाबूजी, गृहस्थ धर्म है, देश का काम और भी बड़ा धर्म है। छोटा धर्म बड़े धर्म को रोकेगा यह पता होता तो मैं शादी न करता।'' अर्थात् देश का स्वार्थ मुख्य है। देश का आजादी आन्दोलन मुख्य है। उसके बाद व्यक्ति की जरूरत, परिवार की जरूरत। सोवियत पार्टी के संविधान में था मेम्बरों के लिए पार्टी का स्वार्थ प्रमुख, व्यक्ति का स्वार्थ गौण। कॉमरेड शिवदास घोष ने दिखाया था यह है मूलत: बुर्जुआ मानवतावादी मूल्यबोध। उन्होंने दिखाया था कि नवम्बर क्रान्ति के समय इसी नैतिकता ने काम किया था, क्रान्ति के बाद भी काफी कुछ दिनों तक इसी नैतिकता ने काम किया। चीन में इसी नैतिकता ने काम किया, क्योंकि चीन की क्रान्ति ही थी, साम्राज्यवाद-सामंतवाद के खिलाफ। फिर कॉमरेड शिवदास घोष ने दिखाया कि यद्यपि क्रान्ति की तैयारी में सत्ता पर कब्जा करने के समय और बाद में समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माण करने के एक स्तर तक क्रान्ति का स्वार्थ प्रमुख मुख्य और व्यक्तिगत स्वार्थ गौण–यह नैतिकता सहायक के तौर पर काम करते हुए भी बाद के दौर में समाजवादी अर्थव्यवस्था की व्यापक तरक्की और स्थायित्व हासिल करने के फलस्वरूप इसी अवधारणा ने 'समाजवादी व्यक्तिवाद' को जन्म देकर समाजवाद के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। इस स्तर पर उन्नत कम्युनिस्ट मूल्यबोध की जरूरत थी जो होता है व्यक्ति को सिर्फ व्यक्तिगत सम्पत्ति का ही खात्मा नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में 'प्राइवेट प्रोपर्टी मेंटल कॉम्पेक्स' को तिलांजलि देकर समाज, क्रान्ति और पार्टी के स्वार्थ के साथ एकात्म हो जाना। मैंने इस शिक्षा का उल्लेख सिर्फ सरसरी तौर पर लेकिन प्रासंगिक संदर्भ के रूप में किया है।

नवम्बर क्रान्ति की नीति का निर्धारण

खैर जो भी हो, मैं जो कह रहा था वह है फरवरी क्रान्ति में मजदूर वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रहने पर भी मजदूर वर्ग सत्ता पर काबिज नहीं हो सका। बुर्जुआ वर्ग ने सत्ता हथिया ली मेन्शेविकों की गद्दारी की बदौलत। आपको मालूम होना चाहिए कि शुरूआती दौर में दो कारणों से ज्यादातर सोवियतों को मेन्शेविक कन्ट्रोल करते थे। एक है बोल्शेविक जार की फौज के खिलाफ सड़क पर लड़ाई में व्यस्त थे, लेकिन मेन्शेविक नहीं थे। उस समय जब विभिन्न जगह कई स्वत:-स्फूर्त: ढंग से ही सोवियत गठित हो रही थी उसमें बोल्शेविक ज्यादा पहलकदमी नहीं ले पाये इस मौके का फायदा उठाकर मेन्शेविकों ने ज्यादातर सोवियतों पर कब्जा कर लिया। इसके साथ एक और विषय की तरफ भी लेनिन ने ध्यान आकर्षित किया था उन्होंने दिखाया था कि जो मिल-कारखानों में लम्बे अरसे से काम कर रहे थे उनमें एक सर्वहारा चेतना थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर को ही जार ने प्रथम विश्व युद्ध में मोर्चे पर भेज दिया था। लिहाजा वे मैदान-ए-जंग में थे। उनकी जगह जिन्हें कारखानों में मजदूरों के तौर पर नियुक्त किया गया था, वे नये-नये गांवों से आये हुए थे। इसका मायने है वे पहले किसान थे लेकिन अब मजदूरों में तब्दील हो गए थे। चूंकि किसानों में पेटी-बुर्जुआ मनोभाव रहता है, इसलिए इन नये मजदूरों में भी उसका प्रभाव था। इनसे पहले जिस तरह के मजदूर थे उस तरह के सर्वहारा ये नहीं थे जिन्हें युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया था। गांव से आये इन नये मजदूरों में से बहुसंख्यक हिस्सा सोवियतों का सदस्य था। इन दो कारणों से शुरूआती दौर में सोवियतों में बोल्शेविकों का बहुमत नहीं था। इसलिए सोवियतों में मेन्शेविकों का बहुमत था और उन्होंने फरवरी में बुर्जुआ वर्ग के हाथों में सत्ता सौंप दी। इस समय भी लेनिन ने असाधारण दक्षता के साथ मार्क्सवाद को लागू किया। नवम्बर क्रान्ति की सफलता के पीछे मुख्य कारणों को रेखांकित करते हुए उन्होंने खुद कहा था कि नवम्बर क्रान्ति को जो मौका मिला था वह दूसरे देशों में क्रान्तियों को नहीं मिल पाएगा, हमेशा ही विभिन्न देशों की क्रान्तिकारी परिस्थितियों में फर्क होता है। उन्होंने दिखाया था कि रूस में पहली बात तो प्रथम विश्वयुद्ध चल रहा था और साम्राज्यवादी दो गुटों में बंट कर युद्ध कर रहे थे। फलस्वरूप वे एकताबद्ध होकर रूस की क्रान्ति में बाधा नहीं डाल सकते थे। यह एक मौका था। दूसरी बात, युद्ध में रूस का जार परास्त हो रहा था। जार के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद और फ्रांसीसी साम्राज्यवाद की दोस्ती थी, जबकि साम्राज्यवादी जर्मनी उनके खिलाफ लड़ रहा था। युद्ध में जार की हार के साथ-साथ युद्ध की वजह से पूरा रूस अकाल की गिरफ्त में आ गया था। इस हालत में लोग युद्ध नहीं चाहते थे, रोटी और शांति चाहते थे। फलस्वरूप क्रान्ति का नारा ही था रोटी चाहिए, शान्ति चाहिए, आजादी चाहिए और भूदासों के हाथों में जमीन चाहिए। व्यक्तिगत आजादी और भूदास को जमीन दो के नारे तो बुर्जुआ जनतांत्रिक क्रान्ति के नारे थे। इन नारों के आधार पर ही फरवरी क्रान्ति विजयी हुई थी। लड़े मजदूर-किसान और आम लोग लेकिन मेन्शेविकों के विश्वासघात की वजह से सत्ता बुर्जुआ वर्ग के पास चली गई। उस समय लेनिन ने दिखाया था कि रूसी बुर्जुआ वर्ग सत्ता में आने के बाद युद्ध से पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि इसे जारी रखे हुए है। बुर्जुआ शासक जो गल्ले के मालिक अर्थात् अनाज के व्यापारी थे उनसे अनाज जब्त करके भूखे लोगों को देने का काम नही कर रहा है। यह बुर्जुआ सरकार जार के साथ, सामंतवाद के साथ समझौता कर रही है इसलिए जमीन जोतने वालों को जमीन नहीं बांट रही है। यह दिखाते हुए कि बुर्जुआ वर्ग विश्वासघात कर रहा है सोवियतों में व्यापक प्रचार और वैचारिक संघर्ष चलाते हुए मेन्शेविकों को परास्त करके बोल्शेविक सोवियतों में बहुमत में हो गये। लेनिन ने जो ध्यान दिलाया था वह है कि फरवरी क्रान्ति के बाद भी जनता में क्रान्ति का जोश बरकरार था। तब भी जो लोग लड़ाई लड़े थे वे बंदूक लेकर घर नहीं लौटे थे। उनके कंधों पर बंदूकें अभी भी थी। लड़ाई का जज्बा उनमें अभी भी बरकरार था। इसलिए वे समझ सके कि अब सत्ता दखल करने का यही सही वक्त है। सोवियतों में उन्होंने समझाया कि बुर्जआ केरेन्स्की सरकार, मेन्शेविक और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी विश्वासघात कर रहे हैं। ये तुम्हारे स्वार्थ के खिलाफ काम कर रहे हैं। चूंकि राज्यसत्ता पर बुर्जुआ वर्ग काबिज हो गया था। लेनिन ने व्याख्या दी कि चूंकि ''रूस में राज्यसत्ता एक नये वर्ग, मसलन पूँजीपति वर्ग और बुर्जुआ बन गए भूपतियों के हाथों में आ गई है कि टू दैट एक्सटेंट बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन इज कमप्लिटेड (उस हद तक बुर्जुआ जनवादी क्रान्ति पूरी हो गई है)।'' (अप्रैल थीसिस) इसलिए उन्हें समाजवादी क्रान्ति कर देनी चाहिए। पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति का आह्वान किया गया था। उन्होंने यह भी व्याख्या की कि किस वर्ग के द्वारा किस वर्ग को राज्यसत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा इस बात को लेकर क्रान्ति का स्तर तय होगा। चूंकि फरवरी क्रान्ति के बाद राज्यसत्ता पर बुर्जुआ वर्ग ने कब्जा कर लिया था, इसलिए बुर्जुआ वर्ग को सत्ता से उखाड़ फेंकने का मायने ही है पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति। लेकिन यह समाजवादी क्रान्ति विकसित पूँजीवादी देशों की समाजवादी क्रान्ति जैसी नहीं होगी। इस सर्वहारा क्रान्ति को बुर्जुआ जनवादी क्रान्ति के अधूरे कामों को सम्पन्न करना होगा। इसलिए अकाल पर काबू पाने के लिए, अनाज के व्यापारियों के हाथों में मौजूद खाद्यान्नों को जब्त करके भूखों मर रहे लोगों में बांटने के लिए, ट्रेड अर्थात् व्यापार-वाणिज्य को कन्ट्रोल करने के लिए क्रान्ति के बाद लेनिन की जीवित अवस्था में वार कम्युनिज्म की नीति अपनायी गई थी। ऐसा बहुत कुछ किया गया था। यह दौर खत्म होने के बाद न्यू इकनोमिक पालिसी (एनईपी) चालू की गई थी। समाजवादी राज्य का नियंत्रण बनाये रखते हुए उस नीति के तहत बुर्जुआ वर्ग को कुछ सुयोग-सुविधाएं दी गई थी, पूँजीपतियों को मिल-कारखाने लगाने का मौका दिया गया था। उस समय ऐसी हालत थी। वार कम्युनिज्म का, न्यू इकनोमिक पोलिसी (एनईपी) का ट्रॉटस्की ने विरोध किया था। ट्रॉटस्की ने तो समाजवादी क्रान्ति का भी यह कहकर विरोध किया था कि रूस जैसे पिछड़े देश में समाजवादी क्रान्ति नहीं हो सकती। लेनिन ने कहा था कि पहले चरण में मजदूर-किसानों की मैत्री, उसके बाद मजदूर-गरीब किसानों की मैत्री होगी। ट्रॉटस्की ने कहा था कि मजदूरों की किसानों के साथ मैत्री नहीं हो सकती, सिर्फ मजदूर वर्ग अकेले ही क्रान्ति करेगा। ये सब नाना विषय लेकर ट्रॉटस्की, जिनोवियेव, कामानेव आदि के साथ लेनिन का काफी मतभेद हुआ था। इन सब विवादों पर लेनिन के साथ स्तालिन डट कर खड़े रहे और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेनिन ने दिखाया था कि एक और फेक्टर ने भी नवम्बर क्रान्ति में काम किया था। वह है रूस एक विशाल देश है और यातायात व्यवस्था बहुत ही पिछड़ी हुई थी, इसलिए लम्बे अर्से तक गृह युद्ध चलाना संभव हुआ था।

लेनिन ने आत्मसात किया था मार्क्सवाद का सारतत्व

मार्क्सवाद को सही ढंग से लेनिन ने समझ लिया था और सही तरह से इस्तेमाल कर पाये थे अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर विचार करने के क्षेत्र में, रूस की

(शेष पृष्ठ 7 पर)

लेनिन और नवम्बर क्रान्ति

(पृष्ठ 6 का शेष)

परिस्थिति पर विचार करने के क्षेत्र में और इस प्रक्रिया में मार्क्सवाद को और भी विकसित व उन्नत किया। बुर्जुआ अवधारणाओं का मुकाबला करते हुए वे इस बात को स्थापित कर सके थे कि रूस में क्यों मार्क्सवाद की जरूरत है। साथ ही साथ प्लेखानोव, ट्रॉटस्की, और ऐसे ही अन्यों की गलत अवधारणाओं का मुकाबला करते हुए उन्होंने मार्क्सवाद की सही समझ प्रदान की। कॉमरेडों को उनकी यह भूमिका भी समझनी होगी। जिन मुद्दों को मैंने पच्चीस-तीस मिनट की चर्चा में समेट दिया, वे उस समय इतने आसान नहीं थे। यूरोप में, रूस में जो द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय के धुरंधर नेताओं के तौर पर जाने जाते थे, उनके छात्र के रूप में शुरू करके लेनिन उनके भटकावों को समझ सके थे क्योंकि उन्होंने मार्क्सवाद के सारतत्व को आत्मसात किया था। उनके खिलाफ दार्शनिक तौर पर उन्हें लड़ना पड़ा और वे कहां गलत हैं यह साबित करके मार्क्सवाद की सही क्रान्तिकारी समझ दुनिया के सामने पेश की और बदली हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में मार्क्सवाद को कैसे समझना होगा और रूस की सरजमीन पर कैसे इस्तेमाल करना होगा यह सब भी दिखाया। रूस में भी फरवरी क्रान्ति के बाद यही समाजवादी क्रान्ति का समय है, यही हाई टाइम है इस तरह देश की नब्ज समझना, जनता और मजदूर वर्ग के मिजाज या मूड को समझना, गहराई से समझना, सूंघने की शक्ति से समझना कितने ऊंचे दर्जे के मार्क्सवादी चिंतनकार होने से यह संभव है! देखिये, नवम्बर क्रान्ति के आह्वान के समय एक तबके ने कहा था कि मार्क्स ने कहा है कि विकसित पूंजीवादी देशों में पहले क्रान्ति होगी। लेकिन रूस में पूँजीवाद तो उन्नत-विकसित है नहीं! तब यहां क्रान्ति कैसे कामयाब होगी। लेनिन ने उनसे कहा कि तुमने मार्क्सवाद की किताबें तोते की तरह रट ली हैं, लेकिन मार्क्सवादी विचार-विश्लेषण पद्धति नहीं समझते हो। पूँजीवाद के असमान विकास की वजह से साम्राज्यवादी युग में पिछड़े हुए देश में पूँजीवाद पहले वाले युग की तरह विकसित नहीं हो सकता। इसके अलावा, बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियां पिछड़े या अविकसित देशों को उन्नत-विकसित होने ही नहीं देगी। इसलिए आज के युग में औद्योगिक क्रान्ति बुर्जुआ वर्ग के नेतृत्व में पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। इस युग में केवल मजदूर वर्ग ही औद्योगिक क्रान्ति पूरी तरह से सफल कर सकता है। लेनिन को उन दिनों ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे वैचारिक संघर्ष करने पड़े थे। नवम्बर क्रान्ति को समझना है तो लेनिन की इस अनन्य भूमिका और योगदान को अच्छी तरह समझना होगा।

रचनात्मक व जीवन्त होनी चाहिए मार्क्सवाद की समझ

मार्क्सवाद की सही व्याख्या करने और प्रयोग के बारे में बताने में लेनिन कैसे सफल हो सके? यहां व्यक्ति की भूमिका समझने की जरूरत है। लेनिन लेनिन बनकर पैदा नहीं हुए थे। स्तालिन, माओ त्से-तुंग, शिवदास घोष में से कोई भी जन्मजात प्रतिभा लेकर पैदा नहीं हुआ। किसी युग का कोई भी महापुरुष जन्मजात प्रतिभा लेकर पैदा नहीं हुआ। प्रतिभा भी एक प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रग्ल (संघर्ष की उपज) होती है। कॉमरेड शिवदास घोष ने 'सुबोध बैनर्जी की याद में' चर्चा में यह व्याख्या करते हुए कहा है कि क्षमता, प्रतिभा लेकर कोई नहीं पैदा होता है। कहा कि एक विशेष समाज में, एक सही क्रान्तिकारी या प्रगतिशील विचारधारा अपनाकर जीवन के सभी क्षेत्रों में सही ढंग से संघर्ष कौन कितना कर पाता है, उसी पर निर्भर करता है उनकी क्षमता, योग्यता, प्रतिभा कितनी निर्मित होगी। लेनिन के शिक्षक जहां फेल हो गए थे, लेनिन वहां इस लड़ाई को लड़ते हुए ही सफल हुए और क्रान्ति सफल की। यह तमाम दुनिया को लगभग असम्भव लगता था, उस समाजवादी क्रान्ति को वास्तव में सफल कर दिखाया था। यह कर दिखाने का काम कोई बहुत आसान नहीं था। बहुत ही मुश्किल था। मार्क्सवाद की किताबें पढ़ने से ही यह होगा नहीं। इसी वजह से कहा जाता है कि मार्क्सवाद है रचनात्मक विज्ञान। स्कॉलर भी बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन तोतारंटन्त करके विद्या से यह चलेगा नहीं। क्या आप मार्क्सवादी दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हो? क्या आप द्वंद्वों पर गौर करते हो? जैसे डाक्टर रोगी के रोग का निदान करता है, क्या उसी तरह आप समाज के रोग को समझ पाते हो? क्या आप वर्गद्वंद्व को समझ पाते हो? कैसे बुर्जुआ वर्ग अपनी विचारधारा और संस्कृति से हमला कर रहा है। इन हमलों को निरस्त करने के लिए सर्वहारा को किस तरह लड़ना होगा? नये-नये हालात में कैसे मार्क्सवादी विज्ञान को रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल करना होगा? वस्तुओं के अन्दर विभिन्न द्वंद्वों की प्रकृति क्या हैं? एक देश में ये द्वंद्व क्या रूप अख्तियार कर रहे हैं? पार्टी के अन्दर भी विभिन्न कॉमरेडों की चेतना का स्तर क्या है? कॉमरेडों के मानसिक क्षेत्र में द्वंद्व कैसे काम कर रहे हैं? कैसे एक कॉमरेड बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच द्वंद्व में डावांडौल हो रहा है? उस कॉमरेड की कैसे मदद करे? प्रति पल द्वंद्व कैसे प्रतिफलित हो रहे हैं? बाहरी द्वंद्व और अन्दरूनी द्वंद्व क्या है? उनमें से प्रधान द्वंद्व क्या है? उसमें भी प्रधान पहलू क्या है? समय बदलने के साथ इन द्वंद्वों में क्या-क्या परिवर्तन हो रहे हैं? –इन सबको समझ पाना, पकड़ पाना ही है मार्क्सवाद को रचनात्मक रूप से लागू कर पाना, जीवंत ढंग से प्रयोग कर पाना है। इसलिए मार्क्सवाद को समझना है तो जीवंत रूप से समझना होगा। और जीवंत रूप से समझना है तो जीवन में प्रयोग करना होगा। किसी ने जिस हद तक भी मार्क्सवाद को समझा है, उसे अपने जीवन में लागू करना होगा। जो जिस हद तक जीवन में लागू करता है, वह उस हद तक उच्च संस्कृति का अधिकारी बनता है, जिस हद तक कोई उच्च संस्कृति हासिल करता है, उसकी मार्क्सवाद की समझ भी उतनी ही उन्नत होगी। इसी तरह लगातर आगे बढ़ना होगा। किस समय कौन सी मांग उठाने से, कौन सा कार्यक्रम लेने से, कौन सी लड़ाई का आह्वान करने से जनता सुनेगी, रेस्पोन्स देगी, प्रत्युत्तर देगी–यह स्टडी (अध्ययन) करना, समझना सभी कुछ है विभिन्न द्वन्द्वों और उनकी प्रकृति को समझना। दूसरे शब्दों में, एक विशेष समय के विशेष द्वन्द्व को विशेष तौर पर समझना। लेनिन जैसे समझ पाये थे, फरवरी क्रान्ति के बाद बुर्जुआ वर्ग विश्वासघात कर रहा है, लेकिन लोग चाह रहे हैं रोटी, शांति, जमीन और आजादी। बुर्जुआ वर्ग यह सब दे नहीं सकता, दी भी नहीं जिसके लिए लोग चिल्ला रहे थे। मेन्शेविक भी विश्वासघात कर रहे थे। उस समय तक रूस में लगभग सभी जगह सोवियतें बन गई थी। वहां भाषण देते हुए लेनिन और उनके सहयोद्धाओं को सोवियतों को विस्तार से यह सब समझाना पड़ रहा था। इस तरह सोवियतों में बोल्शेविक जो अल्पमत थे, वे बहुमत में आ गये थे। इसके बाद नारा बुलंद किया कि 'समस्त सत्ता सोवियतों को' (ऑल पावर टू सोवियत्स)। बुर्जुआ वर्ग ने हथियारबंद ताकत लेकर हमला किया, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी के आह्वान पर मजदूर वर्ग ने बुर्जुआ वर्ग को परास्त किया, नवम्बर क्रान्ति विजयी हुई।

अन्दर से समाजवाद के लिए खतरे के बारे में लेनिन ने दी थी चेतावनी

17 नवम्बर 1917 को नवम्बर क्रान्ति विजयी हुई थी। लेकिन उसके कुछ अर्से बाद महान लेनिन गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए। केवल 53 साल की उम्र में 21 जनवरी 1924 को उन्होंने अंतिम साँस ली। लेकिन इस थोड़े से अर्से में ही वे वास्तविक परिस्थिति पर गौर करके समाजवाद के लिए भावी संभावित खतरे के बारे में सावधान कर गए थे। उन्होंने कहा कि सत्ता से हटा दिये जाने पर (यानी क्रान्ति के बाद) पहले की तुलना में बुर्जुआ वर्ग का प्रतिरोध दस गुना बढ़ जाता है और पूँजीपति वर्ग की ताकत (एक देश में ही सही) न केवल साम्राज्यवादी-पूँजीवादी शक्तियों के साथ इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मजबूती और स्थायित्व में निहित है, बल्कि छोटे पैमाने के उत्पादन के साथ-साथ आदतों की ताकत (बुर्जुआ और सामंती दोनों) में भी निहित है। उस समय दुनिया में छोटे पैमाने का उत्पादन बहुत ही व्यापक था। छोटे पैमाने का उत्पादन पूँजीवाद और बुर्जुआ वर्ग को अनवरत रूप से आये दिन हर घड़ी स्वत:स्फूर्त ढंग से और व्यापक तौर पर जन्म देता रहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि नये वर्ग को (सर्वहारा वर्ग को) (सत्ता से हटा दिये गये) बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ सर्वहारा अधिनायकत्व के जरिये अत्यंत दृढ़प्रतिज्ञ, कठोर होकर लड़ाई करते जाना होगा।

उन्होंने एक और जगह बोला है कि करोड़ों लागों की आदत की (बुर्जुआ-सामंती) ताकत अत्यंत भयावह खतरनाक ताकत होती है। समाजवाद जिस बुर्जुआ प्रतिक्रान्ति के द्वारा आक्रान्त हो सकता है, एवं क्या-क्या कारण से आक्रान्त हो सकता है और सचेत ढंग से प्रतिरोध नहीं कर पाने से प्रतिक्रान्ति विजयी हो सकती है –यह लेनिन के उत्तराधिकारी स्तालिन, माओ त्से-तुंग और शिवदास घोष भी अलग-अलग पहलुओं से बाद में दिखा गए हैं।

विरोध दिवस...

(पृष्ठ 3 का शेष)

भिवानी (हरियाणा) : ए.आई.एम.एस.एस.) भिवानी जिला कमेटी ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया और उपायुक्त भिवानी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पहले स्थानीय नेहरू पार्क में सभा की। इसकी अध्यक्षता संगठन की जिला अध्यक्ष कॉमरेड बिमला जांगड़ा ने की। एसयूसीआई (सी) के जिला सचिव कॉमरेड रामफल ने मुख्य वक्तव्य रखा। सभा में सैकड़ों महिलाएं शामिल थी।

वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं पर बढ़ते अपराध आज सभी समझदार नर-नारियों के लिए चिंता का विषय हैं। चण्डीगढ़ में लड़की का पीछा करने व अपहरण की कोशिश जैसे शर्मनाक काण्ड ने एक तरफ यह साबित कर दिया है कि प्रदेश की राजधानी चण्डीगढ़ जैसे शहर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो गांव-देहात, कस्बों और छोटे शहरों का हाल क्या होगा यह आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ, इसने भाजपा का असल चाल-चरित्र-चेहरा जनता के सामने उजागर कर दिया है। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या 'अच्छे दिनों' का वादा करके केन्द्र व राज्य में सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी की, सभी के शासनकाल में महिलाओं पर अत्याचार व अपराध बढ़े हैं। बेतहाशा बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम करने और महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कारगर कदम उठाने की बजाय सरकार महिलाओं को ही लक्ष्मणरेखा न लांघने का पाठ पढ़ा रही है। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' 'ऑपरेशन दुर्गा' जैसे नारे थोथे साबित हो रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की रोकथाम करने और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए जोरदार सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन गठित करने की जरूरत पर बल दिया।

भिवानी में प्रदर्शन करती हुई ए.आई.एम.एस.एस. कार्यकर्ता

प्रदर्शन की अगुवाई संगठन की जिला अध्यक्ष कॉमरेड बिमला जांगड़ा, उर्मिला, संतरा, कृष्णा, मुनेश, सावित्री, बाला, ब्रह्मा, अनिता आदि ने की।

मुरादाबाद में प्रदर्शन करती ए.आई.एम.एस.एस. कार्यकर्ता

8 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at New Delhi PSO on 7-8 and 22-23 Fortnightly , Date of Publication : September 5, 2017
सर्वहारा दृष्टिकोण
7 से 21 सितम्बर, 2017

एआईएआईएफ की सभा आयोजित

हैदराबाद : उत्तर कोरिया पर साम्राज्यवादी ताकतों के सरगना अमेरिकी साम्राज्यवाद की युद्ध तैयारियों और धमकियों के खिलाफ अखिल भारतीय साम्राज्यवाद-विरोधी फोरम (एआईएआईएफ) की हैदराबाद नगर कमेटी ने 27 अगस्त को जनसभा आयोजित की। सभा में लगभग सौ छात्र-नौजवानों ने शिरकत की।

शुरूआत में उत्तर कोरिया में उन्नत जीवन स्तर और 1950-53 के दौरान डीपीआरके पर अमेरकी हमले में हुई तबाही को दिखाने वाली एक लघु फिल्म दिखाई गई। सभा की अध्यक्षता एआईएआईएफ आंन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना के सचिव कॉ. सीएच मुराहरि द्वारा की गई। जनसभा को गीतम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और एआईएआईएफ आंन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना कमेटी के सदस्य श्री जानी बाशा और एआईएआईएफ आंन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना कमेटी के सदस्यों श्री मधु व सोफ्टवेयर इंजीनियर विजय सिन्हा व अन्य कई लोगों ने भी सम्बोधित किया।

सिरसा डेरा कांड पर न्यायालय के फैसले का एसयूसीआई(सी) ने किया स्वागत

रोहतक : 28 अगस्त 2017, एसयूसीआई(सी) के हरियाणा राज्य सचिव कॉ. सत्यवान ने सच्चा सौदा नामक सिरसा के कुख्यात डेरे के एक खतरनाक माफिया अड्डे में बदलने पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रैस को जारी बयान में उन्होंने कहा कि बेरोकटोक दुराचार, श्रद्धालुओं की आस्था की हत्या और मानव सभ्यता-संस्कृति पर काले कारनामों को लम्बे अर्से से संगठित रूप से अंजाम दिया जा रहा था जो अब एक गंभीर नासूर बन कर फूटा है। कॉ. सत्यवान ने कहा कि यह महज भाजपा सरकार की ही नाकामी का मामला नहीं है। असल में भाजपा द्वारा पूरे राजनैतिक प्रबंधन, पुलिस-प्रशासन तंत्र को डेरा प्रमुख स्वयंभू 'मैसेंजर ऑफ गॉड' के हाथों गिरवी रखने का नतीजा है। लोगों की जान-माल की भारी कीमत पर भाजपा सरकार द्वारा भक्तों की भीड़ रूपी संगठित गिरोह को इकट्ठा होकर खुलकर अपनी मनमानी करने में छतरी प्रदान करने, कानून की आंखों में धूल झोंकने, यहां तक कि जनहित में दिये गए उच्च न्यायालय के आदेशों को भी विफल करने में अपनी पहल और काबिलियत दर्शाई है। एसयूसीआई(सी) ने इसमें संलिप्त सरकार व प्रशासन के टाप कर्ताधर्ताओं के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में एक पीठ से इनकी पूरी छानबीन कराने की भी मांग की। सर्वविदित है कि पिछले चुनावों के समय सत्ता-लिप्सा पूरी करने के लिए समाज, राष्ट्र, मानवीय सरोकारों, नारी मर्यादा की सुरक्षा की कीमत पर भाजपा ने सिरसा के इस कुख्यात डेरे से अपने समर्थन में वोट डालने का जो फतवा जारी कराया था, वह सौदा हरियाणा, पंजाब समेत समाज व देश के लिए महंगा साबित हुआ है।

तमाम धमकियों व बाधाओं के बावजूद इस डेरा काण्ड में कोर्ट की विवेकपूर्ण सराहनीय भूमिका व दोषी डेरा प्रमुख को दण्डित किये जाने के बावजूद खतरा टला नहीं है। लम्बे अर्से से रची हुई माफिया-गिरोह शक्ति व उसका आधार बरकरार है। दीन-दुखी, गरीब, लाचार व जीवन में घोर अनिश्चितता से ग्रसित विशाल जनसमूह को ठगने, उनमें अंधविश्वास व कटुता पनपा कर उन्हें जीते-जागते मानव-यंत्र में ढाल कर आज्ञाकारी भीड़ में बदलने में डेरे का सफल प्रयोग कैंसर का रूप ले चुका है। धर्म व अध्यात्म की आड़ में भगवान व गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा-आस्था को भुना कर एक तरफ बेशुमार दौलत, वैभव लूटने के इस माफिया अड्डे और दूसरी तरफ राजनीति की इससे सांठगांठ के खिलाफ यदि समाज व राष्ट्र उठ खड़ा नहीं होगा, तो अच्छे दिनों की कल्पना करना भी दुश्वार हो जाएगा। यह सामाजिक विवेक, इतिहास-बोध, तर्कशील मन व ज्ञान-विज्ञान के बल पर एक सामाजिक-सांस्कृतिक सशक्त आन्दोलन के द्वारा ही सम्भव है जिस झण्डे को हमारे देश में नवजागरण के अग्रदूतों, राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर व ज्योतिराव फूले आदि ने पहले पहल उठाया था। यह स्थिति सभी से आत्म मंथन कर अपनी पहल करने की मांग करती है। एसयूसीआई(सी) इस हेतु अपने संकल्प को पुनः दोहराती है।

कश्मीर घाटी में नागरिक की कायराना हत्या व धारा 35 ए रद्द करने के कदम में सरकार की संलिप्तता की एसयूसीआई (सी) ने की कड़ी निन्दा

26 अगस्त, 2017 को एसयूसीआई (सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया:

कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 21 अगस्त 2017 को कथित तौर पर एक फर्जी मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना द्वारा एक नागरिक की अति कायराना हत्या की हम घोर निन्दा करते हैं। काश्मीर में हंदवाड़ा की फोरेस्ट रेंज हफरूदा में पुलिस द्वारा गोलियां से छलनी शव बरामद किया गया। ऐसी नृशंस हत्याओं को तुरन्त रोका जाना चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकारों को कथित घटनाओं की जांच करानी चाहिए, आर्मी/पुलिस अधिकारी जो ऐसी तथाकथित मुठभेड़ों के मुख्य अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर में लम्बे अरसे से जारी विस्फोटक स्थिति को शांत करने के लिए और आजादी के बाद कश्मीर के भारत में अधिमिलन के दौरान दिये गये विशेष अधिकारों और किये गये वायदों के निरन्तर उल्लंघन की वजह से व्यथित और उत्तेजित कश्मीरी लोगों के भरोसे को पुनः बहाल करने के लिए जहां केन्द्र सरकार की तरफ से तुरन्त आवश्यक राजनैतिक पहलकदमी लेना जरूरी था, वहीं इसकी बजाय संविधान की धारा 35 ए जो जम्मू-कश्मीर राज्य विधान सभा को राज्य के 'स्थाई निवासियों' को परिभाषित करने का अधिकार देती है और उन स्थाई निवासियों को विशेष अधिकार और सुविधायें प्रदान करती है को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया के जरिए सरकार ने मुद्दे को और भी जटिल बना दिया है। कुछ गुमराह लोगों द्वारा पीआईएल दायर करने जैसा एक कदम जिसे शासक पार्टी का परोक्ष समर्थन मिल रहा है यह स्पष्ट रूप से उन अलगावादी कट्टरपंथी ताकतों को मौका प्रदार करेगा जो भारत सरकार के खिलाफ वाजिब कारणों की वजह से कश्मीरियों के बढ़ते असंतोष व आक्रोश का फायदा उठाकर भारत-विरोधी भावनाएं भड़का रहे हैं और भड़काऊ नारों के साथ तथा सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की सुनवाई के दिन राज्य में बन्द बुलाने जैसे कृत्यों के जरिये उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। निस्संदेह इससे स्थिति और भी खराब होगी और ज्यादा हिंसा होगी, जान-माल का नुकसान होगा और सबसे गम्भीर है कि कश्मीरी लोगों का भारत से अलगाव बढ़ेगा।

इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वह 35ए को रद्द करने के कदम से खुद को अलग कर ले, सेना को अनावश्यक कार्रवाइयों को अंजाम देने से रोके जिनके चलते कश्मीरी लोग और ज्यादा शत्रुतापूर्ण होते जा रहे हैं, काले कानून आफ्स्पा (एएफएसपीए) को रद्द करे तथा बिना कोई और समय गंवाये घाटी में शान्ति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए और कश्मीरी के लोगों का भरोसा पुनः जीतने के लिए सरकार सकारात्मक वातावरण पैदा करे।

हम सभी सही सोच रखने वाले जनवाद पसंद लोगों का भी आह्वान करते हैं कि वे नागरिकों की ऐसी जघन्य हत्याओं की निन्दा के साथ-साथ घाटी में पहले से ही विस्फोटक स्थिति को और भी बदतर करने वाले भड़काऊ कदमों की भी निन्दा करें, और अपनी पांतों की एकता को और भी सुदृढ़ करें ताकि बीजेपी-नीत केन्द्र सरकार को ऐसी अंधाधुंध हत्याओं मे लिप्त होने से रोका जा सके और संविधान की धारा 35 ए को निरस्त करने के तिरस्कारपूर्ण कदम को वापस लेने के लिए मजबूर किया जा सके।

आन्दोलन की जीत

बर्खास्त आंगनबाड़ी कर्मियों की बहाली

हरियाणा सरकार ने 2017-18 के वार्षिक बजट में आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में 1072 रुपये की बढ़ोतरी की थी। परन्तु 15 मार्च 2017 को सोनीपत के इंजीनियरिंग कॉलेज में महिला सम्मान समारोह के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने उपस्थित डेढ़ हजार आंगनबाड़ी कर्मियों के समक्ष जब यह कहा कि हाल के वर्ष में आपके मानदेय में 640 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। मुख्यमंत्री महोदय अनजाने में नहीं कह रहे थे, उनको पता था इस 1072 रुपये की बढ़ोतरी को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। आंगनबाड़ी कर्मियों ने जब मुख्यमंत्री को 1072 रुपये बढ़ोतरी बताने को कहा तो मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि 640 रुपये बढ़तरी ही आपको मिलेगी। इस वायदा खिलाफी ने आंगनबाड़ी कर्मियों को झकझोर कर रख दिया क्योंकि 3 वर्ष से मानदेय में बढ़ोतरी पहले ही बन्द पड़ी थी। नाराज आंगनबाड़ी कर्मी मुख्यमंत्री की सभा से उठकर हाल से बाहर बैठ गई। मुख्यमंत्री फिर कहने लगे कि बाकी वृद्धि केन्द्र के बजट से पूरी कर दी जायगी। जबकि केन्द्र की देनदारी पर 5 वर्ष से रोक लगी हुई है। बाल विकास मंत्री ने रोष व्यक्त करने वाली 4 आंगनबाड़ी कर्मियों को बर्खास्त कर दिया तथा 1482 के खिलाफ 'शो कॉज नोटिस' जारी कर दिये। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन हरियाणा बर्खास्त कर्मियों की बहाली की मांग को लेकर 7 जून 2017 से सोनीपत में अनिश्चित धरना चला रही थी। 22 अगस्त से हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के कार्यकर्ता भी आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठ गए। आखिरकार 1 सितम्बर को सरकार ने आन्दोलन के दबाव में चारों बर्खास्त कर्मियों को बहाल कर दिया। इस आन्दोलन में एआईयूटीयूसी के कॉ. ईश्वर सिंह राठी और संयुक्त कर्मचारी मंच के प्रांतीय अध्यक्ष आर.के. नागर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन की प्रांतीय नेता पुष्पा दलाल, बिमला नैन व शीला मीन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सोनीपत : एआईयूटीयूसी के नेतृत्व में 21 अगस्त को विरोध प्रदर्शन करती हुई आंगनबाड़ी कर्मी

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."

Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com फोन नं. : 011-25726631, 9868350503